भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1824
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनाएं
1824. डॉ. सी. एम. रमेशः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन योजनाओं की योजना-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्या है; और
(ग) इन उपायों से राज्य में किसानों की उपज में सुधार और आय बढ़ाने में कितना योगदान मिला है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) भारत सरकार आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में कृषि के संपूर्ण क्षेत्र जैसे क्रेडिट, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसानों का समूह, सिंचाई, विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में क्रियान्वित की गई कृषि से संबंधित योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की योजना-वार वित्तीय प्रगति **अनुबंध-II** में दी गई है, जबकि योजना-वार वास्तविक प्रगति **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए उपायों से कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में फसल-वार उत्पादकता का स्तर **अनुबंध-IV** में दिया गया है। इसके अलावा, किसानों की आय पर इन योजनाओं का प्रभाव निम्नानुसार देखा जा सकता है:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 ऐसे किसानों की सफलता की कहानियों का एक संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अपनी आय में दोगुने से अधिक की वृद्धि की है।

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई 2018-जून 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौरे (जनवरी 2019-दिसंबर 2019) के दौरान कृषक परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) आयोजित किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति कृषक परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस का 70वां दौर) के ₹6,426 से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस का 77वां दौर) में ₹10,218 हो गई है।
- घरेलू उपभोग व्यय (2023-24) पर एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रुपए में)	
	वर्ष 2011-12 एनएसएस (68वां राउन्ड)	2023-24
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के % के रूप में अंतर	83.9	69.7

अनुबंध।

कृषि क्षेत्र में राज्यों को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
10. स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवाईवी)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

अनुबंध II

पिछले तीन सालों में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जारी की गई धनराशि का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	मिशन/योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
		रिलीज	रिलीज	रिलीज
क	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-डीपीआर	45.79	86.33	63.75
2	कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	47.45	-	46.65
3	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	222.82	105.8	239.5
4	सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी	-	4.20	6.45
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	2.50	-	3.51
6	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	-	9.70	17.91
ख	**कृषोन्नित योजना**			
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	-	10.53	32.91
2	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)	-	17.65	98.87
3	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस)	-	3.00	11.19
4	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	50.00	24.00	51.13
5	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	6.50	6.33	6.25
6	बीज एवं पौध सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	0.36	3.38	5.64
7	डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (डीएएम)	-	5.00	5.92
8	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	-	-	0.19

अनुबंध III

आंध्र प्रदेश में योजनाओं की वास्तविक प्रगति

योजनाओं का नाम	**वास्तविक प्रगति**
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	आज तक, 21 किस्तों के माध्यम से 19,121.14 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसमें से 21वीं किस्त के दौरान 39,15,504 लाभार्थियों को 783.10 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)	32,408 किसान पंजीकृत किए गए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)	बीमा कंपनियों ने ₹5,580.1 करोड़ के के दावों का निपटान किया है।
एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)	5,663 परियोजनाओं के लिए 3,030 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 5,128 करोड़ रुपये है।
10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	714 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत किए गए हैं।
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)	5 परियोजनाओं के लिए 190.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	वर्ष 2024-25 के दौरान, 87,303.25 मीट्रिक टन खोपरा, चना, मूंग, तुअर और उड़द की खरीद की गई है, जिसकी कीमत ₹669.33 करोड़ है।
प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है और 3,192.49 करोड़ रुपये की सहायता राशि (केंद्रीय हिस्सा) जारी की गई है।
कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	किसानों को 2,79,515 से अधिक कृषि मशीनें वितरित की हैं।
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	जैविक खेती के तहत 3.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 7.47 लाख किसानों को लाभ हुआ है।
सॉइल हेल्थ एंड फर्टीलिटी (एसएचएंडएफ)	1,63,06,877 के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1,58,32,830 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	69,524 हेक्टेयर को कवर किया गया है और 123.97 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक, इस योजना के तहत 5,60,545 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	6.21 लाख किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है और प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय बीज भंडार में 2.21 लाख क्विंटल बीज संग्रहित किए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)	विगत तीन वर्षों के दौरान 95,157 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदर्शन किए गए, 56,417 क्विंटल बीज वितरित किए गए और 32,673 क्विंटल बीज का उत्पादन हुआ।

एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)	60 लाख टन से अधिक क्षमता वाली 1551 भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सब्सिडी के रूप में 31,936.74 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 तक, 74 लाख टन क्षमता वाली 1634 कोल्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, 19,626 बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है, 997 नर्सरियों की स्थापना की गई है और 11.08 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम	जनवरी 2026 तक 91,906 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) –तिलहन	2024-25 के दौरान तिलहन के तहत 4.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन	45,33,556 किसान पहचान पत्र जारी किए गए हैं।
राष्ट्रीय बांस मिशन	42 हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्र को बांस वृक्षारोपण के अंतर्गत लाया गया है और 288 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अनुबंध IV

आंध्र प्रदेश में प्रमुख फसलों की उत्पादकता:

(किलोग्राम/हेक्टेयर में)

फसल	2022-23	2023-24	2024-25
चावल	3730	3822	3928
मक्का*	4046	4007	4524
बाजरा	2027	2097	2310
रागी	1185	1261	1456
स्मॉल मिलेट्स	860	902	848
तुअर	323	413	475
सूरजमुखी	834	886	963
कुल तिलहन	937	889	1031
गन्ना	73893	80533	90242
कपास	372	297	476

* ख़रीफ़ सीज़न के लिए उत्पादकता

स्रोतः यूपीएजी पोर्टल

*****